the first report of the Ninth Finance Commission together with an Explanatory Memorandum as to the action taken on the recommendations of the Commission (in English and Hindi versions).

Now it is 2.58. So the Private Members Business will go up to 5.28, because that time we cannot curtail. That time will be given to that.

RESOLUTION REGARDING GENERATION OF INCREASED GROWTH RATE FOR SPEEDY DEVELOPMENT OF THE COUNTRY—CONTD.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Mrs. Pachouri, you can continue.

3.00 P.M.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उप सभाध्यक्ष जी, पिछले समय मैं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात कर रहा था। सातवीं पंचवर्षीय योजना आर्थिक परिवेश में प्रारंभ हुई, जिसका प्रारूप 9 नवम्बर, 1985 को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने बनाया और जिसका प्रमुख जो लक्ष्य था, वह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था और इसमें इस बात को दर्शाया गया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा और उसमें यह दर्शाया गया था कि कृषि उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाएगा। कृषि उत्पादन प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन में 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जब कि छटवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन में केवल 5.5 प्रतिशत वृद्धि ही संभव हो सकी। इसी प्रकार खनिज की वृद्धि का लक्ष्य 8.3 प्रतिशत रखा गया था। सातवीं योजना में औद्योगिक विकास कार्यक्रमों के लिए ऊर्जा आपूर्ति की वृद्धि दर 12.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया। मान्यवर, इस योजना में आई कमी की तरफ मैंने पिछली बार बोलते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया था क्योंकि मेरी अपनी मान्यता है कि वर्तमान योजना मंत्री आदरणीय माधवसिंह सोलंकी काफी निपुण हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं कि वे इस प्रकार की प्लानिंग तैयार करेंगे जिससे कि वह आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप होगी और देश की तरक्की और विकास होगा। मुझे आदरणीय सोलंकी जी की क्षमता पर पूरा भरोसा है इसलिए मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रतापूर्वक ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

मान्यवर, पिछली बार मैंने ग्रोथ रेट का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट तय किया गया, वह प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि छटवीं पंचवर्षीय योजना का जो ग्रोथ रेट है वह 5.2 हो। दुर्भाग्य से 5.2 का जो ग्रोथ रेट छटवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किया गया था, वह पूरा नहीं हो पाया। इसलिए कुछ आशंका है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का ग्रोथ रेट 5 प्रतिशत हो पाएगा। इस बात की ओर मंत्री जी ध्यान दें।

साथ ही जो परिव्यय का आधार वर्ष था उसकी तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया कि इस योजना के उद्देश्य पत्र में 84-85 को बेस इयर बनाया गया जबकि योजना आयोजन ने योजना का जो प्रलेख तैयार किया है, उसमें 84-85 के स्थान पर 85-86 को योजनागत विनियोग हेतु आधार बनाया है। । मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा किया जाना एक विसंगति का द्योतक है। इस पर भी

□[श्री सुरेश पचौरी]

विचार किया जाना काफी जरूरी है। मुद्रास्फीति की समस्या भी इसमें आती है कि वास्तविक घाटे की वित्त व्यवस्था इस राशि से अधिक होगी जोकि सातवीं योजना में करीब 1400 करोड़ रुपए की वित्त व्यवस्था द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरुरत है।

महोदय, जहां लक्ष्यों की पूर्ति का सवाल है उसमें कुछ शंकाएं हैं जो अपने आप में संदिग्ध हैं। जैसेकि योजना आयोग ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 130 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त 107 लाख हैक्टेयर की वर्तमान सिंचाई क्षमता का उपयोग भी किया जाएगा। चूंकि अभी जो सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं इसलिए उससे इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी इसमें मुझे कुछ शंकाएं नजर आ रही हैं।

मान्यवर, जो संकल्प आदरणी सुब्रम्हण्यमस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रायरिटी दी है। उसमें इस बात को दर्शाया गया है कि उसकी वजह से छटवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट बढ़ा। मान्यवर, मैंने पिछले समय भी कहा था कि 1979 से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी आई है जबकि जनता सरकार राज कर रही थी। उसकी कमी का सूचकांक 140 था। इसी प्रकार 78-79 में एक्सपोर्ट में भी घाटा हुआ था। यह 1063.48 करोड़ रुपये का था। इसलिए उनका यह दावा भी ठीक नहीं है कि जो बल उन्होंने एग्रीकल्चर पर दिया था, उसके आधार पर छटवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट बढ़ा था। इस प्रकार मैं यह कह सकता हूं कि 1977-78 और 1979-80 में जबकि जनता सरकार दिल्ली के तख्त पर राज कर रही थी, जबकि जनता सरकार सत्ता में थी वे वर्ष किसी भी प्रकार से आर्थिक उपलब्धियों के वर्ष थे, इस बात को मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं। मान्यवर, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जिनका जिक्र करना मैं अपना कर्त्तव्य समझूंगा क्योंकि उससे बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जहां तक कि पर-केपिटा इन्कम की बात है, जब कि हमने करंट प्राइसिज को बेस माना है तो यदि हम यह आंकड़े देखें तो 1980-81 में 1,557.3 करोड़ रुपए हुए। इसी प्रकार से 1981-82 में 1,743 करोड़ रुपए हुए जबकि 1985-86 में 2,595.6 करोड़ हुई। यह अपने आपमें इस बात का संकेत है कि हमारी योजना कितनी प्रभावी है जब कि उस समय जब कि छठी पंचवर्षीय योजना थी और जब कि जनता शासन विशेष रुप से ढाई वर्ष राज कर रही थी, उस समय क्या स्थिति थी।

जहां तक प्रोडक्शन की बात है फूड ग्रेन् वगैरह की बात है, वह आंकड़े भी मैं आपके सामने देना उपयोगी समझूंगा खरीफ और रबी की फसल के संबंध में 1978-79 में खरीफ का जो एरिया मिलिन हैक्टेयर था वह 82.85 था। इसी प्रकार जो प्रोडक्शन मिलियन टन था वह 78.08 था। इसी प्रकार जो यील्ड हैक्टेयर पर किलोग्राम था वह 942 था, साथ ही रबी का जो एरिया मिलियन हैक्टेयर था वह 46.16, प्रोडक्शन मिलियन टन 53.82 और यील्ड पर

हैक्टेयर किलोग्राम 1166 था । जब हम यह आंकड़े 1979-80 देखते हैं तो खरीफ का हमको एरिया मिलियन हेक्टेयर 80.79, प्रोडक्शन मिलियन टन 63.25 और यील्ड पर-हैक्टेयर किलोग्राम 783 देखने को मिलती है । इसी प्रकार रबी का एरिया मिलियन हेक्टेयर 44.42, प्रोडक्शन मिलियन टन 46.45 और यील्ड पर-हैक्टेयर किलोग्राम 1046 देखने को मिलता है जब कि जनता शासन राज में, जब जनता-पार्टी के लोग सत्ता में थे और जब 1985-86 के आंकड़े हम देखते हैं खरीफ के तो एरिया मिलियन हैक्टेयर 81.55, 85.99 प्रोडक्शन मिलियन टन और 1054 यील्ड पर-हैक्टेर किलोग्राम देखने को मिलता है । इसी प्रकार रबी के आंकड़े देखते हैं तो 45.51 एरिया मिलियन हैक्टेयर, 64.48 प्रोडक्शन मिलियन टन और 1417 यील्ड पर-हैक्टेयर किलोग्राम देखने को मिलता है । जहां तक पर-केपिटा फूड-ग्रेन्स की एवेलेबिलिटी का सवाल है जब हम 1978; 79 और 1980 के आंकड़े देखते हैं और 1984, 85 और 86 के आंकड़े देखते हैं तब भी हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश को फूड प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में कांग्रेस को प्रमुख भूमिका रही जब कि समय-समय पर इन्दिरा जी और राजीव जी प्रधानमंत्री के रूप में सर्वोच्च पद पर थे ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1979 में जो पर-केपिटा एवेलेबिलिटी थी फूड-ग्रेन्स की, जैसे चावल की तो 200.3 प्रति दिन थी । गेंहू की जब हम देखते हैं तो 132.3 ग्राम प्रतिदिन थी और जब हम 1986 के आंकड़े देखते हैं तो राइस की जो उपलब्धता है पर-ग्राम प्रतिदिन वह 218.9 और गेंहूं की 147.1 । सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह सोशल इकानोमिक कंडीशन की है जिससे कि किसी भी देश की तरक्की, किसी भी देश का विकास, किसी भी देश की उन्नति आंकी जा सकती है । मान्यवर, हमारे लिए जो लाइफ एक्सपिटेंसी है जो यदि हम वर्ष के हिसाब से देखें तो 1984-85 में 56.1 रही आदमियों के लिए और औरतों के लिए 57 रही लेकिन जो हमने निर्धारित लक्ष्य किया है 1999 का और 2000 तक का वह मर्दों के लिए 63.3 और औरतों के लिए 64.7 निर्धारित किया है। डेथ रेट 1984-85 में प्रति हजार 11.9 था जब कि 1999-2000 का हमारा टारगेट 8.2 है । जी. डी. पी. 1984-85 में 2016 था और हमारा लक्ष्य 4163 है । जब हम 7वीं योजना को देखते हैं तो उसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए, उनको खुशहाल बनाया जाए । जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी संख्या यदि आप देखें तो यह 37 प्रतिशत है जो 2000 तक 15 प्रतिशत रह जाएगी। इसी प्रकार से ऐंप्लायमेंट अपार्चनिटीज का जहां तक सवाल है, वह 1984-85 में जहां 187 थी 1999-2000 में बढ़कर 318 होगी । मैंने ये आंकड़े इसलिए प्रस्तुत किए हैं कि आदरणीय स्वामी जी ने इस बात का जिक्र किया था कि इस सरकार की जो वर्तमान योजना नीति है और जो हमारी 8वीं, योजना है उसका सही आधार पर आंकलन नहीं किया गया है । उसको चाइनीज पालिसी के अनुसार, जनता पार्टी की उपलब्धियों को मद्देनजर रखकर बनाया जाए । इसीलिए हमने जनता

□[श्री सुरेश पचौरी]

सरकार के दौर में क्या उपलब्धियां हुई, उसके आंकड़े प्रस्तुत किए ।

वर्तमान में यह जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें प्रमुख खर्च ऐग्रिकल्चर के लिए किया गया है । चरण सिंह जी की पालिसी का जिक्र माननीय स्वामी जी ने किया कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम कितनी प्राथमिकता ऐग्रिकल्चर को देते हैं । यदि हम उस समय के बजट को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेगें कि उस समय के बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है । अभी भारत सरकार ने जो बजट राजी जी के नेतृत्व में रखा है उसमें ऐग्रिकल्चर के लिए 12095 करोड़ रुपया रखा गया है । इसी तरह से गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम है, चाहे वह आइ. आर. डी. पी. हो आर. एल. ई. जी. पी. हो, आर. एल. इ. यू. हो, उसमें हम देखें तो पता चलेगा कि आइ. आर. डी. पी. के लिए 346 करोड़, एन. आर. इ. पी. के लिए 529 करोड, आर. एल. इ. जी. पी. के लिए 730 करोड़ रुरल वाटर सप्लाई और सेनिटेशन के लिए 430 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । यह गांवों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है । इस काम के लिए ऊर्जा का विशेष रूप से उपयोग किया जा सकता है । ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों के लिए पहले कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था और काफी कम बजट रखा जाता था । लेकिन अभी जो बजट में उसके लिए प्रावधान किया गया है वह 9196 करोड़ रुपए का है । इसी प्रकार पावर के लिए 3963 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । मैं ये सारी बातें इसलिए आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिससे देश की जनता इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी बात को कहना आसान है, लेकिन उसको मूर्तरूप देना कठिन काम है । किसी नीति को कहना आसान है लेकिन उसका क्रियान्वयन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और जवाबदारी की बात है । जहां हमारी पार्टी हमारी सरकार राजीव जी के नेतृत्व में नीति की घोषणा करती है, वहीं यह भी सुनिश्चित करती है कि उसको सही समय पर क्रियान्वित किया जाए, मूर्त रूप दिया जाए ।

जहां तक हैल्थ और फैमिली वैलफेयर की बात है, उसमें भी 828 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है । वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 235 करोड़ रुपए का प्रावधान है ।

महोदय, योजना आयोग के संबंध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें योजना आयोग का प्रमुख हाथ रहता है । और उसमें सुधार पाने के लिए कुछ सुझाव बड़े अदब के साथ प्रस्तुत करना चाहूंगा । मेरी यह मान्यता है कि जो प्लानिंगकमीशन है उसको एक इंडो-पेंडेंट आर्गेनाइजेशन होना चाहिए । इसके कई भाग, उपभाग बन गए हैं और कई मंत्रालयों से सम्बद्ध कर दिया गया है इस कारण वह अपने आप को जमा नहीं पाता । कई बार योजनाएं बनाई जाती हैं और उसके लिए जो जानकारियां आमन्त्रित की जाती है वह पर्याप्त समय में हम को नहीं मिल पाती है इसलिए मेरा कहना है कि इसके ढांचे में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है । उसमें उन लोगों को लिया जाना चाहिए जो इन विषयों के विशेषज्ञ हों और जो इन विभागों से सम्बन्ध रखते हों ।

जैसे चाइना और दूसरे देशों का जिक्र किया गया मैंने यह कहा था कि हर देश की परिस्थितियां, हर देश की स्थितियां, हर देश की समस्या, हर देश की कठिनाइयां भिन्न होती हैं। जब हमारा योजना आयोग इस तरह की योजना बनायें तो उसको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ही बनायी जायेंगी। अगर पंचवर्षीय योजनाएं देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनायी जायेंगी तो ज्यादा फलदायी साबित हो सकती है। ऐसा मेरा विचार है। इसलिए यह आवश्यक है कि अन्य विभाग के विस्तार को कम करने की भी ज्यादा जरूरत है।

एक बात आदरणीय स्वामी जी ने कही थी कि उन को चाइना की लीडरशिप, चाइना की संस्कृति और चाइना के नेतृत्व पर गर्व है। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। कोई किसी भी देश की संस्कृति पर, किसी भी देश के नेतृत्व पर गर्व कर सकता है। अच्छा होता अगर वह भारत के सम्बन्ध में अपनी अभिव्यक्ति करते कि भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के नागरिकों के बारे में उनका अपना क्या ख्याल है। अगर वह गर्व प्रकट नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मत तो व्यक्त कर सकते थे। मुझे अफसोस है जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो भारत के सम्बन्ध में उन्होंने सम्मान की या गौरव की कोई बात नहीं कही। साथ ही उन्होंने कुछ और भी बातें उठायीं जो अपने आप में एक मत नहीं है चाहे थ्योरी की हो, थिसीज की हो, मेल नहीं खातीं। एक तरफ वह फ्री मार्किट की बात करते हैं और एग्रीकल्चर के बढ़ावे की बात करते हैं और दूसरी तरफ गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन इकोनोमी की बात करते यह अपने आप में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाती। पंडित नेहरू की पालिसी का उन्होंने जिक्र किया। पंडित नेहरू का विशेष जोर इस बात के लिए था कि जहां देश के विकास, एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन बढ़ाने की बात हो वहां इस बात पर जोर हो कि इंडस्ट्रियल प्रोडेक्शन भी तेज हो, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगें। जबकि चरण सिंह जी प्रमुख रुप से इसके खिलाफ थे जो कि अपने आप में जमींदारों के प्रवक्ता माने जाते थे। जब बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री लगेंगी तो उसके साथ एंसिलियरी में छोटी इंडस्ट्रीज भी लगेंगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी जो पंचवर्षीय योजना बनी थी उसका जो प्रमुख आधारस्तम्भ था वह गांधीयन फिलोसफी पर था, पंडित नेहरू के विचारों पर था। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे नेता देश के प्रधान मंत्री ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि एड प्लान को जहां वह प्रारुप देने जा रहे हैं उसमें आम आदमी का इन्वाल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। पीपल्स इन्वाल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। जो प्लानिंग हो वह निच ले स्तर से ब्लाक लैविल से शीर्ष स्तर तक का इन्वाल्वमेंट हो। उसके लिए डिबेट भी अलग-अलग की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की, चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंगें की। निर्वाचित प्रतिनिधियो के भी इस बारे में ब्यूज जाने। बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो पीपल्स रिप्रजेन्टेटिव की बात है, पीपल्स इनवाल्वमेंट की बात है यह अपने आप में एक सराहनीय कदम है। योजनाएं बनती हैं और योजनाएं बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उनका इम्पलीमेंटेशन। योजना का इम्पलीमेंटेशन तभी हो सकता है जब

[श्री सुरेश पचौरी]

हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना में सहभागी कर सकें, भागीदार बना सकें। इस बात को भी देखना जरूरी है कि यह योजना जिस मकसद के लिए बनायी गयी थी वह मकसद पूरा हुआ या नहीं, उसका इम्पलीमेंटेशन हुआ या नहीं और उससे कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया गया। जो बेनिफिसरीज हम सेलेक्ट करते हैं वे सही बेनिफिसरीज हैं या नहीं, जिनको लाभ मिलना चाहिए वे उसके हकदार हैं या नहीं, यह काम लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जन-प्रतिनिधि का है। इसलिए हमारे देश में प्लानिंग की जो शुरूआत हो रही है और हमारे नेता श्री राजीव गांधी और श्री सोलंकी जी के मंत्रित्व काल में हमारी योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले सकें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। एन्टी-पावर्टी प्रोग्राम को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ-साथ आई. आर. डी. पी., आर. एल. ई. पी., एन. आर. ई. पी. और डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए. आदि अनेक कार्यक्रम हमने बनाए हैं। इसके साथ-साथ वालन्टरी एजेंसीज को भी हमने इसमें इंवोल्व किया है। वीमन और चाइल्ड केयर प्रोग्राम को भी मूर्त रूप देने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा हैल्थ प्रोग्राम, इरीगेशन और वाटर प्रोग्राम और शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के वेलफेयर के कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। इन सब में वालन्टरी एजेंसीज को शामिल किया गया है। इससे भी अधिक महत्व-पूर्ण जो बात है वह यह है कि देश की जनता के हित के लिए यह जरूरी है कि डिसेन्ट्रेलाइज प्लानिंग होना चाहिए। इस-को मद्देनजर रखते हुए पंचायती राज की बात सामने आई है। पंचायती राज का सपना इसी चीज को सामने रखकर किया गया था क्योंकि भारत गांवों का देश है। हमारे देश की 70 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है। गांवों के लोगों का उत्थान करने के लिए पंचायती राज की परिकल्पना की गई थी। इसलिए यह जरूरी है कि हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा महत्व दें और योजनाओं में उनका सह-योग लें।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, क्या कोई समय की सीमा भी है?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : यह तो प्राइवेट मेम्बर का प्रस्ताव है। इसमें सीमा नहीं हो सकती है।

श्री सुरेश पचौरी : इसलिए हमें ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और ब्लाक पंचायतों को पर्याप्त शक्ति देनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी योजना का जो उद्देश्य है उसका पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसका प्रोपर ढंग से मोनिटरिंग भी होना चाहिए। पंचायती राज की कल्पना को जिस तरीके से साकार रूप देने का प्रयत्न सरकार की तरफ से किया जा रहा है वह सराहनीय कदम है। लेकिन उसमें जो कमियां है उनको दूर करने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। सातवीं योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन है और हमारा जो सर्वहारा वर्ग है उसका उत्थान करना है। यदाकदा जो हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं उनको भी पूरा करने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। हम आपनी आठवीं योजना बनाने जा रहे हैं। वह हमारी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगी जिससे इस देश के आम आदमी, इस देश के सर्वहारा वर्ग और गरीब मजदूरों को, किसानों को, अपना उत्थान करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

THE .VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : I would like to inform the hon. Members that the Resolution cannot be carried to the next Session. It has to be completed today. If it is not completed today, it lapses. Members are interested to know the views of the Government. Therefore, I would like to know from the hon. Minister how much time he will take for his intervention.

THE MINISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI MADHAV-SINGH SOLANKI) : About half-an-hour

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Therefore, at 4.45 p.m., we shall ask the hon. Minister to intervene. I will not be here. But I hope the hon. Minister will clarify the news-item which appeared in the 'Patriot' about MRTP Act and FERA.

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी यहां पर उपस्थित नहीं हैं । उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है । स्वामी जी का केरेक्टर · · · (**व्यवधान**) ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इसका जिक्र न कीजिए ।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं । उनका स्वभाव कुछ चुलबुला है, यह चुलबुलापन इनके प्रस्ताव में भी थोड़ा-सा निखरा है । उनकी दृष्टि और देशों पर जमी हुई है नीतियों में, विचारों में, उनको और देशों की संस्कृति, और उनका आयोजन भला-भला लगता है । और वह अपने आप में देख नहीं सकते हैं, मैंने इसीलिए इन शब्दों का चयन किया है । जहां तक हमारी आयोजनाओं का संबंध है, आजादी के पश्चात्

नेहरू जी एक दृष्टा थे और उन्होंने जब आयोजनाओं की बात की तो उन्होंने संपूर्ण तरीके से एक भारत के मूलाधार को लेकर ऐसी आयोजनाओं को चलायया। इंदिरा जी ने उसको आगे बढ़ाया और राजीव गांधी जी उसको और आगे ले जाने में प्रयत्नों में है । इस प्रकार हमारी विचारधारा या कांग्रेस पक्ष की विचारधारा किसी देश पर निहित नहीं है । किसी देश की अर्थव्यवस्था को सामने रखकर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं । मान्यवर, अब मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं । मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं । मैं आशा करता हूं कि वे अपने कार्यकाल में देश की आयोजनाओं को एक नई दिशा देने में जरूर सफल होंगे । बातें कर लेना अलग बात है लेकिन अगर उसको स्वरूप देना हो तो वह दूसरी बात है । जब तक पोलिटिकल विल न हो तब तक हम इसको अच्छे ढंग से कारगर नहीं कर सकते हैं मुझे आशा और विश्वास है कि वे इसमें सफल होंगे । हमारी कांग्रेस पार्टी भी मान्यवर, बहुत दिनों से इस पर लगातार लगी हुई है । पंचायती राज के बारे में अभी पचौरी जी ने बात की है कि किस तरह से उसको कारगर बनाया जा सकता है । इस संबंध में हमारा पक्ष भी बहुत विचार कर रहा है ।

मान्यवर, 1981 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का 76.3 प्रतिशत लोग यानी 52 करोड़ के अधिक लोग 5.76 लाख गांवों में बसते हैं । उनमें भी मान्यवर, एक हजार से कम जनसंख्या के गांवों की संख्या 78.5 है । देश को सूखे तथा भुखमरी से बचाने के लिए जिन्होंने अपना पसीना धरती को देकर धान उगाया है ये सब इन 6 लाख गावों के वासी तथा 55.37 मिलियन

☐ [श्री मीर्जा ईर्शादबेग]

लैंडलेस लेबरर्स हैं जो कि मान्यवर अनपढ़ तो हैं लेकिन अज्ञानी नहीं हैं । देश की ऐसी जनआबादी, उनको कृषक कहिए, किसान कहिए या अगर उन पर खुश हो जाएं तो उनको जगत तात कहिए लेकिन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के पाट के बीच उनको न्याय प्राप्त नहीं हुआ है । उसको उचित स्थान देने के लिए, उसके विकास के लिए जो भी कदम उठाए जाएं वे दूसरे अर्थों में देश के विकास के कदम हैं । उनको न्याय दिलाने के संबंध में मैं राष्ट्र के इस महान सदन के सम्मुख कुछ मांगें प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

मान्यवर, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अन्य किसी भी उत्पादक क्षेत्र के कार्य से अधिक है । 70 प्रतिशत जनसंख्या को इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है और 45 प्रतिशत राष्ट्रीय आय इस क्षेत्र से प्राप्त होती है । भारतीय अर्थ-व्यवस्था में जब तक कृषि क्षेत्र सबल होने के साथ-साथ गतिशील नहीं होगा तब तक इस देश में संतुलित आर्थिक विकास की संभावनाओं की वास्तविकता में परिणत करना दुष्कर होगा । मान्यवर, सरकार ने समय-समय पर उचित कदम उठाकर किसानों को सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है । यह उचित अवश्य है लेकिन समुचित नहीं है । हमारी आ-योजना में कृषि का व्यक्तिगत हिस्सा दूसरी योजना में 20.9 प्रतिशत, तीसरी योजना में 20.5 प्रतिशत, चौथी में 23.3 प्रतिशत, पांचवीं और छठी योजना में 22.1 प्रतिशत रहा और मान्यवर सातवीं योजना में इसका प्रतिशत 23.8 रहा । यह कम है और इसको आगे बढ़ाने की मैं मांग करता हूं । किन्तु मान्यवर, बैंकों के रूल्स से लेकर प्राधान्यता तक के अफसर वर्ग ने किसानों को उद्योगपतियों से निम्न समझा जब कि कारखानों में 1981 में 7.11 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त था और कृषि क्षेत्र ने 153 मिलियन लोगों को रोजगार दिलाया था । मान्यवर, 1983 में कृषि मजदूर की आय 415 बनी जबकि अन्य क्षेत्रों में मजदूर की आय 1216 बनी ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): May I have the leave of the House to request Dr. Kidwai to occupy the Chair ?

The Vice-Chairman (Dr. Mohd. Hashmi Kidwai) in the chair.

श्री मीर्जा ईर्शादबेग : डा. किदवई साहब मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस आसन को आज संभाला है ।

श्री राम चन्द्र विकल : पूरे हाउस का मुबारकबाद है ।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : भारत सरकार के कर्मचारी सही मायने में सब छुट्टियां मिला कर के एक साल में फकत 6 महीने काम करते हैं और उनके सप्ताह में काम करने के घंटे 33 है और कम से कम वेतन प्रति वर्ष 9000 रुपये से लेकर एक लाख 8 हजार रुपये तक है जबकि कृषि मजदूर के वेतन की मात्रा फ़कत 4225 रुपये सालाना है । समय समय पर सरकार ने सपोर्ट प्राइस घोषित किये हैं । इतना ही नहीं राज्य सरकारों के इरीगेशन ड्यूज 660 करोड़ से अधिक है । एक हजार करोड़ रुपये तक यह डयूज गवा रही है । दो हजार से अधिक उर्वरकों पर सबसिडी दी जा रही है और बैंकों के कर्जों का भुगतान का 50 प्रतिशत किसानों का आज ओवर

ड्यूज है। बाढ़ और सूखे से ग्रस्त कृषि की उपज की मात्रा इनपुटस के बढ़े हुए दामों में संतुलन नहीं कर पाती है। इसलिए इन सब उपायों के बावजूद भी किसान आज गरीब से और गरीब होता जा रहा है। इसके विपरीत सीमांत तथा छोटे किसान बने हैं। मान्यवर, कृषि उपज की मात्रा ही कम है यह बाजार तक कैसे पहुंच सकेगी। जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है इसमें बीच के मध्यमी आज भी सवार हैं। एक तरफ उपभोक्ता रोता है कि दाम उंचे हैं और दूसरी तरफ किसान रोता है कि दाम नीचे हैं। इन बीच की एजेंसियों को जितना दूर किया जाए उतना ही किसान और उपभोक्ता लाभान्वित होगा। इसको करने का अगर कोई उपाय है तो वह है सहकारिता। सहकारिता को एक आन्दोलन के रूप में जब तक नहीं अपनाया जाएगा देश में तब तक हमारी आर्थिक अवस्था जो कृषि बेस्ड है उसमें हम सुधार नहीं ला सकेंगे। ग्रामीण विकास के लिए मैंने पहले कहा कि सहकारिता आन्दोलन की इसमें अनिवार्य आवश्यकता है। इसका फ्रेम वर्क क्या है? आज 94 हजार प्राथमिक सहकारिता क्रेडिट सोसायटियों के बेस में से आज भी सिर्फ 40 हजार के पास अपने गोदाम उपलब्ध है। इस सहकारिता का योगदान क्या है? आज भी सहकारिता द्वारा देश के गन्ना क्षेत्र में 60 प्रतिशत योगदान है, 20 प्रतिशत उर्वरक उत्पादन में इसका योगदान है और एग्रो इंडस्ट्रीज को मात्रा दो हजार की है। कोआपरेटिव क्रेडिट 32 सौ करोड़ से अधिक आज दिया जा रहा है। ए० पी० एम०सी० ने तीन हजार करोड़ रुपये के माल का व्यापार किया है और 15 सौ करोड़ से अधिक की अन्य वस्तुएं उर्वरक इत्यादि का वितरण किया है। यह हम देख सकते हैं कि आज तक देश के लोगों तक खास कर के ग्रामीण व्यवस्था जो है उसमें कितनी हमारी पहुंच हुई है। आज किसान को क्या मिल रहा है? आज किसान को 61 रुपये प्रति हेक्टेयर से अधिक शार्ट टर्म लोन नहीं मिल पाता है। इनवेस्टमेंट क्रेडिट अडवान्स 133 रुपये प्रति एकड़ आज बनता है और उर्वरक वितरण में सहकारिता का योगदान सिर्फ 42 प्रतिशत होता है। इसका विस्तार जब तक हम नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक दूसरे क्षेत्र जो हैं इस क्षेत्र पर हावी रहेंगे। उर्वरक वितरण में सहकारिता योगदान 42.9 % है। ग्रामीण क्षेत्र का 62 प्रतिशत सहकारिता से आज जुड़ा हुआ है। 1980 तक जिला मध्यस्थ सहकारिता बैंकों के ओवर ड्यूज में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि प्राथमिक सहकारिता में 32 प्रतिशत से 46.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह लैंड डबलपमेंट बैंक हैं उनके ओवर ड्यूज 1969 में 10 प्रतिशत थे और इसकी मात्रा बढ़ कर आज 46 प्रतिशत के करीब पहुंच गई है। यह दृश्य दिख रहा है आज हमारे किसानों का। सहकारिता संगठनों में मारकेटिंग और प्रोसेसिंग विभागों में परस्पर लिंक न होने की वजह से इसके ओवरड्यूज बढ़ते हैं। मैं इसका उदाहरण दूंगा। गुजरात में इसके अच्छे उदाहरण भी है। जो हमारे दूध की व्यवस्था है वह अच्छी है, आयल सीड तथा गन्ना सहकारी क्षेत्रों में भी अच्छी व्यवस्था है। जो इंटर लिंक होना चाहिए यह इन तीन क्षेत्रों में अच्छे ढंग से पाया गया है लेकिन बाकी के क्षेत्र छूट गये हैं। सहकारिताओं के संचालन की जो व्यवस्था है इसमें जो चुने हुए लोग है और उनके जो प्रोफेशनल्स हैं उनको सही ढंग से मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए

[श्री मीर्जा इर्शादबेग]

उस मार्गदर्शन का अभाव है। सहकारिताएं अभी भी छोटे तथा सीमान्त किसानों की सम्पर्क व्यवस्था में, मैं समझता हूं कि आंकड़ों को देखते हुए थोड़ी ओछी दिखती है। मैं एक बात अवश्य उजागर करता हूं कि कृषि क्षेत्र को प्रथम बार रिकग्नाइज करके इसके विभिन्न क्षेत्रों को छूने का प्रयास माननीय राजीव गांधी जी ने किया है। मैं इसके लिए अवश्य उनको बधाई दूंगा । इस वर्ष के बजट में कृषकों को दो से ढाई प्रतिशत बैंक इंटरेस्ट में रियायत, उर्वरकों में प्रत्येक बैग पर 8 रुपये की रियायत तथा कृषि करों के लिए ऋण संबन्धी तीन हजार रुपये का प्रावधान तथा जलधारा कार्यक्रम और जंतुनाशक दवाइयों पर रियायत और नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट रिलीफ़ फंड आदि का जो आयोजन किया गया है, यह देश के कृषकों के उच्चतम हित में है और इसकी बधाई मैं राजीव गांधी जी और उनकी सरकार को देना आवश्यक समझता हूं। 99 लाख टन चीनी प्राप्ति के लक्ष्यांक को सिद्ध करने के लिए अधिक उत्पादन की आज आवश्यकता है और नयी फैक्टरियां जब तक चालू नहीं होंगी तब तक मैं समझता हूं कि इसके उत्पादन को हम और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारा उत्पादन 40.86 लाख टन से कुछ आगे नहीं बढ़ा है। सरकार ने, मान्यवर, एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप बनाया है। मैं सोलंकी जी से एक खास दरख्वास्त करना चाहूंगा क्योंकि गुजरात के मामले में भी कुछ लाइसेंसेज बकाया है। इस पर सरकार ने एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप बनाया है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चीनी उद्योग को इंसेटिव देने के लिए नयी चीनी फैक्टरियां लगाने तथा लाइसेंस नीति पर विचार कर रहा है। मान्यवर, पहले भी समूचे सदन ने चाहे कांग्रेस के पक्ष से संबन्धित माननीय सदस्य हों या विपक्ष, सबने सर्वसम्मति से इस बात को कहा था कि लाइसेंस नीति में सुधार की आवश्यकता है और 1500 से 1800 टी० सी० डी० की सीमा निर्धारित करके नये लाइसेंसेज सहकारिताओं को देने की पूरे सदन ने मांग की थी। मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा रखता हूं कि इस दिशा में जो विचार हैं माननीय सोलंकी जी उनको सरकार के और डिपार्टमेंट्स तक पहुंचायेंगे ।

मान्यवर, फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आज और भी थोड़ी खराब परिस्थिति है । इनके ओवरड्यूज का अभी तक उनको भुगतान नहीं हुआ है। गुजरात के किसानों ने इस पर आन्दोलन चलाया था और गुजरात सरकार ने 214 करोड़ रुपये की एक योजना शेष भुगतानों के लिए यहां पर भेजी है, मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि त्वरित गति से उसको निपटा करके कृषकों की इस बारे में सहायता की जाये । इतना ही नहीं यह बड़े दुख की बात है कि शायद इस दिशा में भी सोचा जा रहा है कि इस योजना को बंद कर दिया जाये । मैं तो आपके माध्यम से इसका और व्यापक विस्तार करने की मांग करता हूं।

माननीय सोलंकी जी इस बात का भी आप आयोजना में ध्यान रखेंगे कि तिलहन, दलहन, आयल सीड्स तथा धान को भी इसमें प्रावधान देकर प्रीमियम रहित बीमा योजना समग्र भारत में लागू कर दी जाये । मैं समझता हूं कि इससे कृषि जो आज एक रिस्क वाला प्रोफेशन माना जाता है वह नहीं

रहेगा और इससे कृषकों को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी ।

मान्यवर, बिजली तथा डीजल पर मिनिमम चार्ज व्यवस्था की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। कृषि को जब तक अद्यतन नहीं बनाएंगे तब तक हमारी आर्थिक व्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था को हम अच्छा सुधार नहीं दे सकेंगे । आज तक तो किसान अपने उसी पुराने ढंग से खेती करता जा रहा है। विज्ञान की जो सीमाएं हैं शायद उसको अभी तक छू भी नहीं पाई हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि प्रति एक हजार हेक्टेयर खेतिहर जमीन के बीच में कम से कम एक अद्यतन साज सज्जित एग्रो सेंटर की आयोजना हो । माननीय सोलंकी जी गुजरात से आते हैं। उनको पता है कि ग्रामीण किसान क्या है उनकी पहुंच क्या है और इसकी व्यवस्था क्या है। मैं आशा करता हूं कि ऐसे एक हजार हैक्टर के बीच में एक एग्रो-सेंटर देकर यह किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचा सकते हैं।

मान्यवर, अब मैं इम्पलायमेंट की बात पर आता हूं। 1981 की जनसंख्या के अनुसार 52.15 करोड़ के करीब ग्रामीण जनसंख्या है, जिसमें आधे से ज्यादा परिमाण युवकों का है। इसलिए आगामी योजना में इस पर लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि सोलंकी जी जब आगामी योजना बनायेंगे तो इस बात पर खास ध्यान रखेंगे ।

मान्यवर, आगामी योजना में प्रति वर्ष 10 मिलियन वर्क अपरचुनिटीज उपलब्ध करवानी पड़ेंगी। अगर इस ढंग से, अधिक गति से हमने विकास करना है और आर्गेनाइज्ड सेक्टर, मीडियम तथा लार्ज-स्केल इंडस्ट्री आदि में 1/2 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रति वर्ष नहीं दे सकते, तो इसके लिए अगर कोई क्षेत्र है तो वह कृषि क्षेत्र है कि जिसमें रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन आप उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर दस मिलियन का हमको लक्ष्य सिद्ध करना है, तो कृषि क्षेत्र को हमको सबसे पहली प्रायर्टी देनी पड़ेगी और इसलिए योजना का संपूर्ण आधार ग्रामीण बेस्ड तथा कृषि-बेस्ड होना चाहिए।

मान्यवर, ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था, यह पंचायत, सहकारिता तथा स्कूलों के माध्यम से ही इसे अधिक कारगर बना सकते हैं। यह तीन आधार स्तम्भ हैं। इनको जितना व्यापक बनायेंगे, जितना इसको सक्षम बनायेंगे, इतनी आर्थिक व्यवस्था हम आगे बढ़ा पायेंगे।

मान्यवर, सहकारिता ही एक ऐसा आंदोलन है कि जिसकी वजह से हम ग्राम के, तथा देश के आर्थिक माध्यम को अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

फार्मर्ज ट्रेनिंग सेंटर्स ग्रामीण क्षेत्रों में बना कर, वैज्ञानिक दृष्टि हम कृषि क्षेत्र को दे सकते हैं। इसलिए मैं मांग करूंगा कि आगामी योजना में इसका आयोजन जरूर होना चाहिए। एक बड़े ब्लाक स्तर पर एक एक्सपर्ट टीम से सर्वे करवाया जाना चाहिए और इसके पश्चात इस ढंग से अगर इसको देखा जाएगा, तो योजना को एक नई गति और नई दिशा मिल जाएगी।

मान्यवर, आज कार्यक्रम तो चलाये जा रहे हैं--- ट्राइसेम के अंतर्गत ग्रामीण ट्रेड का जो चयन होना चाहिए, वह वहां की ग्रामीण अपरचुनिटीज के अनुकूल होना चाहिए, जो आज नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसमें आज जो त्रुटियां रह गई हैं, उनको दूर करें। वहां

[श्री मीर्जा इर्शाद बेग]

का जो ट्रेड है, उसके मुताबिक उसका चयन होने की भी मैं मांग करता हूं।

सहकारी तथा विकास एजेंसियों में आज युवकों को सम्मिलित करने की दिशा में एक स्कीम बनाये जाने की भी मैं मांग करता हूं। मान्यवर, बैंकों का अधिकतम काम रोजगार कार्यक्रमों के संबंध में सही नहीं है। उनको जो लक्षांश भी दिये गये हैं, उनके 70 प्रतिशत की पूर्ति भी वह नहीं कर पाये हैं। वहां के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्ज ने उनको जो चयन करके एप्लीकेशंज भेजी हैं, तो वह भी उसमें से 50 प्रतिशत को भी संतुष्ट नहीं कर पाये हैं।

इसलिए, योजना में जो खामियां हैं, उनको दूर करने की आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं।

आखिर में, मैं समझता हूं कि सोलंकी जी ने इस पर अपने विचार बड़े विस्तृत रूप से पेश किये हैं। मेरी मान्यता है कि इस राष्ट्र के बेस, पंचायत को अगर मजबूत नहीं किया जाएगा, तो दूसरी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हैं कि जिससे सही मानों में गांव के छोटे से छोटे इनसान तक हम उसको एक आजादी को जो एक सुंदर मुखडा है, उसके दर्शन करवा सकेंगे। इसलिए आज मेरी पार्टी भी निरन्तर इस चिंता में है, मेरे लीडर, श्री राजीव-गांधी – वह भी आज इस दिशा में चिंतन कर रहे हैं और मैं इसकी मांग करता हूं कि जब तक कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान का स्वरूप नहीं दिया जाएगा, संविधान में उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, उसको यह अधिकार अगर संविधान में नहीं दिया जाएगा, तब तक पंचायती राज जिस कारगर ढंग से देश में आगे बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ पायेगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पंचायती राज को संविधान के अंदर दाखिल करना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे कि सेंट्रल लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है, इसी तरह से पंचायती लिस्ट बना करके उसको संविधान में सम्मिलित करने की मैं मांग करता हूं। मैं आशा करता हूं कि अगर यह कदम सरकार ले ले, तो मैं समझता हूं कि इस देश के किसानों का उसमें हित है, देश की ग्रामीण जनता का उसमें हित है और देश की आजादी सुरक्षित रखने वाले तो लोग हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का अगर सब से श्रेयस्कर कोई हित है, तो मैं समझता हूं कि इस पंचायती राज को कानून का, संविधान का दर्जा देकर हम इसको अधिक कारगर बना सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Two hon. Members preceded me in speaking on this Resolution today. While Shri Suresh Pachouri who spoke was supposed to speak after me and my good friend Shri Mirza Irshadbaig. ..

SHRI MIRZA IRSHADBAIG. Sir, he was not present. I am very thankful to him.

SHRI G. SWAMINATHAN : He wanted to speak because he had an urgent engagement. Subsequently there are a few lion. Members who also wanted to speak wilier than me, but I think, since I also have got my own engagement, so I am before you.

Sir, this is a very important subject. This, according to me, is beyond politics. Whether you belong to the ruling party,

treasury benches or you belong to the Opposition, whatever party you belong to, it is a subject on which you have to give deep thought and arrive at certain conclusions.

Today none of the Opposition party Members is present. I am the only pet son, I think, present here in the House. So, on behalf of the Opposition 1 have an opportunity to speak a few words on this very important Resolution moved by a Member from the Opposition. My only regret is, when such an important Resolution is moved, we have very few Members present in the House. I am sorry more Members have not taken keen interest on this economic policy which is very important for the nation. last time Dr. Subramanian Swamy spoke on it. I think last time he was not able to speak much when he moved it on 5lh August. This is what I could find from the proceedings of that day. He wanted to speak at length on the Resolution today, but because of the walk-out by the Opposition, he could not do so.

Shri Suresh Pachomi contested many points that had been raised by Dr. Subtamanian Swamy. I know Dr. Swamy is a controversial Member from the Opposition, but from the speech that he made on 5th August, I find he has raised many salient points. I think the hon. Members belonging to any party must view these points dispassionately.

The main thrust of his argument is that during the last 40 years, particularly after the planning process started, the economic growth rate of the country has not been sufficient. It is true that the growth rate in real terms even after the Seventh Five-Year Plan will be only 3.5 per cent or near 4 per cent. He wanted the growth rate to be about 10 per cent. The hon. Prime Minister has stated that the growth rate envisaged during the Eighth Plan is 10 per cent. Dr. Swamy's argument is, if we could not attain the growth rate as anticipated during the last seven Five-Year Plans, how can we achieve this growth rate of 8 per cent during the Eighth Five-Year Plan pursuing the same economic policy? That is the crux of his argument

I think the Government has a bounden duty to answer this argument because if we follow the same kind of economic policy, the same kind of centralised planning, most probably we will not be able to achieve this growth rate. It is becoming very urgent for our country to achieve a larger or speedier growth rate. It is all the more urgent because of the huge unemployment problem facing tbe country. This problem has not been solved by various Five-Year Plans and the backlog of unemployment is growing. Even though percentagewise the figure may look to be less, but in absolute terms the number has been growing very large. Similarly the number of. people below the poverty line percentagewise may, according to the Government, look to be coming down, but in absolute terms the number is increasing because the population growth rate is 2.3 per cent. Here, Sir, I would like to give an argument of Piloo Mody. Once he was a Member of this House. I am told that he asked the then Planning Minister "What was the number of unemployed people in this country during the First Five Year Plan?" The hon. Minister for Planning said "So many crores of people were unemployed during the First Five Year Plan." Then, again, he asked "how many people were unemployed during the Third, Fourth and Fifth Five Year Plans?" The Minister said about the number group. Finally, not more than two interpellations were allowed by the Chairman. He started up giving and the Chairman said "You cannot ask another interpellation, because you already asked two interpellations.'" He said my only final interpellations, how many more Plans would be required to make everybody in this country unemployed." I think, if you know Mody in his witty manner you will understand it. He only pointed out one important thing that with every Plan, more and more people are getting unemployed. I think, it is also relevant to pinpoint this here because we have not solved our unemployment problem. We have, also not solved our poverty problem.

[Shri G. Swaminathan]

In real terms we have not achieved anything. When you go to the villages, you will know about it. The other day, Sir, our hon. Prime Minister toured Tamil Nadu and many of us would have watched on T.V. became 1 come from tbe same place which he toured. He collected a large amount of crowd. He went inside the villages and saw so many places and many of the hon. Members would have also seen on T.V. the poor state of affairs in Tamil Nadu. It is not only in Tamil Nadu but in Bihar, Orissa and other States. also. Honourably the only State, most probably, which has achieved a speedier growth rate was Gujarat from where our hon. Minister comes. But if you take Tamil Nadu or any other State, the poverty-stricken people especially agricultural labourers, yon will find the real poverty which they are living in. If we have not solved their problems during all these 35 years, what is the strategy, the Government is going to adopt ? Is it going to follow the same strategy which it has followed during all the Five Year Plan periods ? It is going to follow another strategy?

The main point is, Sir, when you compare the other countries with India, you will know the actual position.

[The Vice-Chairman (Shri H. Hamimaiithappa in the Chair]

I have travelled abroad many times and, I think many of the hon. Members would have travelled many times abroad. Recently I had been to East Asia and when you see a small country like Hong Kong, the kind of improvement it attained almost every year is something to praise. After two years, you go *to* Hong Kong again and you don't find the same Hong Kong If you go to Singapore you will find the same thing. After recession it is coming up again. If you go to South Korea, you will find the same thing.

Recently I had been to Japan and 1 have travelled widely inside Japan with some of our Indian friends. We cannot say that we could see their prosperity. The kind of prosperity that they are enjoying and the kind of poverty that India is having is something, a comparison should we made. Our hon. Minister should have made many trips to Japan. This country was completely de-vasted after the war. After 1945, it was under the boots of the U.S.A. Those people were starving. They were not having even ordinary clothes to wear. They could not even take bath. Most of the people were having skin diseases because they could not afford to buy a soap. That was the country in 1946. Now, you can see what kind of prosperity Japanese are enjoying. The other day I was travelling from Tokyo to Fujiama hills. There was a lady interpreter who was coming with us. They were not talking anything else except about the prosperity of their country. Sometimes I myself do not feel very happy because immediately I have to remember my country and the poverty in which I am. That lady was saying "Roads that were laid from Tokyo to Fujiama hills were worth crores of rupees." She enumerated that it was something like the Government of India budget and the collection that they were receiving by way of gate collections from cars, lorries and stalls on Tokyo to Fujiama hills road were something like the budget of Tamil Nadu. She was referring to their economic prosperity rather loudly. When we compare South Korea, when we compare Japan, when we compare Singapore, when we compare Hong Kong, you will wonder as to how these countries have prospered *so* much. You compare other countries which are also Asian countries. You compare Burma, which was for 23—25 years under the dictatorship rule. They said that they were under socialism. I do not know what kind of socialism they Were having because I once said in this House that socialism is something which nobody can define.

You have socialist countries, you have communist countries, You have a country like Poland. Recently, I had a friend from Poland. He is an eminent doctor and when we were having dinner together, we were discussing Poland. He was saying that nobody is happy in Poland. With so

many years of communism, so many years of what they call socialism, food riots are happening in Poland. No consumer goods are available. Even workers who are considered to be in a paradise in communist countries, the Walesa and other groups, they are having opposition to ihe very same Government which is considered to be the workers' paradise. When you talk of any country in Europe like Czechoslovakia, Hungary, Yugoslavia, Poland, Burma and even if you take a country like North Korea, which is again another communist country even if you take another country Indonesia under Sukarno, what happened to a country like Ghana under Nkrumah these are all countries which had a certain approach. The approach of these countries, I could very well say, is centralised planning. This was the approach which all there countries had. Take any country which has the communist type of centralised planning and any country which vouches that they will have socilsm or ty whatever name they may call it, even take Britain, Britain before Thatcher and after Thatcher. I had to go to London before Thatcher came in and after Thatcher came in and see the kind of people they had and the kind of prosperity they had. No", those people were not having even whitewash or colour-wash in their houses. That was the condition before Thatihei came into power. I am not an admirer of Thatcher. But what I would only say is that there are only two types of views now prevailing. One kind of view is regarding the centralised planning which they were adopting and we are adopting because we are a poor country. We want that kind of planning which we think will help the poor people. We wank to uplift the people. Suppose, when we try to talk like that, people may say, this mm is capitalist because he talks about capitalism. Another man is socialist and another man is communist. I am talking about pragmatism. I am neither a capitalist nor a socialist. Everybody is interested in the upliftment of the people. We want to know what should be the strategy we should adopt. 2462 RSS 88—9

Then I come to the kind of strategy that Japan has adopted People may say, of Course, Hong Kong is a small country, Singapore is a small country and what is relevant to South Korea may not be relevant to India. I was talking to a senior person, a Secretary. He said, what was relevant to Taiwan may not be applicable to you because Taiwan is a small country. This is the kind of argument. There are many small countries which are very poor. If you take North Korea, it is not as prosperous as South Korea. If you take Taiwan and Sri Lanka, Sri Lanka is a poor country and Taiwan is a rich country. Even within these small countries, there are countries which have certain strategy and which are rich, which are getting richer and which are getting prosperous and their growth rate is about 10 per cent Japan after the war, between 1960 to 1970, during their growing period, their growth rate, in real terms, was 10 per cent growth rate Onless you have a fast growth rate, it is impossible for you even after 2000 AD to develop and you will have the same kind of people below poverty line. And the people who are unemployed, will *bs* there. You will not be able to reduce their number. So, what strategy the hon. Minister is going to adopt ? Sir, I would only say the communist countries, the socialist countries are also realising their kind of plan-? ning, their kind of administering their economy is not very sound. I am talking about USSR. You are very well aware about the recent restructuring, Perestroika and Glasnost in USSR where they have been talking of their economy being libe~ ralised in many ways and we have a folder. If anybody feels that I am not telling the truth, he can even go to our library and take the press clippings indexed on USSR economy and the whole press clippings index I saw the whole liberalisation of the USSR economy from agriculture. We used to be talking about agriculture in USSR where the private plots used to give nearly 50 per cent of the agricultural produce of USSR. Those days, this fact used to be denied. Nowadays. then themselves are saying, it is true. Now, they are allowing them to sell their agricultural

{Shri G. S. Stvaminathan].

produce. Now, the other day, there was a big quarrel here about multi-nationals. They laid, how can you allow multi-nationals ? China is allowing 10,000 multi-nationals within their country and the other day, there was a talk about privatisation of some Government sector company which is losing. There is a big argument, how can India privatise ? How can we go against socialism and Directive Principles ? 1 would like to mention one small clipping. About China also, we have got a full folder on the latter's liberalisation. They are allowing all multi-nationals. They are inviting multi-nationals. Not only they are inviting multi-nationals from European and American countries but they are also inviting the Gulf countries to come there and, they have liberalised the whole economy. *{Interruption).* Unfortunately, nobody is 4.00 P.M.

there. I am the only man talking. I quote this report from "The Times of India", New Delhi, dated 7th August, 1987.

> "While developing countries like India, and to a lesser extent, Pakistan, are engaged in a hair-splitting debate on the efficacy of public sector undertakings, communist China seems to be forging ahead with its own behalf of "privatisation" in a big city."

(Again it says :

> "The "experiment" is said to be part of an innovative move to separate ownership from management. A survey of nearly 6000 Government-owned industrial enterprises, leased to private lessees in six major cities of China, has re vealed that 95 per cent of them are operating satisfactorily."

Six thousand units, they gave them to private people because Government was not able to run them profitably. Profit is not a bad word. Profit is neeessary. You may call it profit or surplus *or* whatever you like, you should create wealth. Only wealth can be distributed. Without creating wealth, how can you distribute ? If we have to distribute whatever we have, then, only the existing wealth, of the country has to be distributed, it is very necessary that India should think of creating wealth in the country. Wealth is not a bad word. In China they are talking, of late, how to make people, the country, wealthy. This is th: very word they are using. This is the slogan in that country now. I want the hon. Minister, the hon. Prime Minister and the Government to think seriously about this. We should also think whether any kind of restructuring of the economy is also necessary. Such restructuring is necessary not only for the USSR but for India too.

As a person who has- had the opportunity to visit Japan, I would like to enumerate a few points about it here. The first point is the land reforms made in Japan in Meiji revolution in the pre-war period. They abolished the Zamindari system. Big landholdings were abolished. Subsequently, after 1945, again they embarked on land reforms. All the tenant-holdings by absentee landlords were taken away by the Government. In India, Sir, we say we have got into land reforms. But still, if you lock into it deeply, there is a lot of *benami* holdings. Recently we passed a Bill on this. I hope if the Act comes into force the big holdings will go away from this country. As a person hailing from an agricultural area in Tamil Nadu I would say, still our land reforms have not taken shape. There are *benami* holdings and tenant holdings which have not been taken away by the Government. In Japan, in 1945 itself all this was done away with. There is no absentee landlord in that country. The reason why agriculture prospers there is that absentee landlordism is thoroughly abolished in Japan. In. India, still tenants and the tillers of the soil are two different people. Sir, I would advise the Government to immediately implement land reforms, not because it is a socialist measure but because it is fundamental for the growth of the country. As already said by hon. Member Mr. Mirza Irshadbaig, who preceded me, you cannot give employment to all tbe people by industry. It is impossible. You can give employment to people only through agriculture to a large extent. Only certain people you can siphon off to in-

dustry. What the economists have teen talking is as if you can siphon off oil the agricultural people to industry and give them employment. Ultimately what has happened? Sir, agriculture has to give more employment. That is what has happened in Thailand and in Japan. If you compare India with Thailand and Japan in respect of the number of people employed in agriculture, you will find three to four times greater number of people there, per acre. Why is it so? Why more people are employed there in the same acreage ? The production that we have in India is not able to sustain the number of people who are employed in agriculture. So only when our per yield increases

that more number of people will get employment in agriculture and that we cart think of providing employment to other people in industry.

The next reform the Japanese made was land reforms, the break-up of Ziabatsu. In 1946 in Japan there were many monopoly houses. These mononolv houses were not allowing any land of internal competition. Tn 1946 there were nine big companies in Japan : Nippon Steel, Mitsui, Mitsubishi, Tokyo Shiboy Company, The Electric Company, Hitachi and other companies. Thev were monopolising the entire Japan and they were not allowing internal competition. These nine companies were broken up by this Ziabatsu principle and internal competition was created. And that was the reason why Japan prospered. Japan prospered because its production developed. The next point is they have given priority to production in their Flans. For them the first and the foremost thing is production. They call it Priority Product in Revolution. The fourth thing is the most important thing, according to me, which ruled their economy but which is quite divorced in our country and that is the 1949 Dodge Proclamation. There was one Joseph Dodge who was a Minister in USA. He was sent by President Truman in 1949 and this gentleman gave certain principles to the Japanese that they should follow in their fiscal economy. I would read out these four basic principles of the Japanese economy. Dodge said :

> "The Japanese people should demand a balanced budget and should they direct their attention to the elimination of excessive expendituies, wastefulness, subsidies, over-employment and the general dependence on government instead of individual of group accomplishment."

This is die first principle of everyone. Now compare India with Japan. In Japan their budget should be balanced; we have an unbalanced budget. In Japan they say, "Direct attention to the elimination of excessive expenditures, wastefulness...." in India we are wasting a lot of money The Japanese say, "eliminate subsidies"; in India we are extending subsidies. In Japan they say, 'eliminate over-employment in government"; here we are having over-dependence on government. Instead of individual or group dependence we are over-depending on government: We say, I want employment from government, I want everything from government. If I do not get anything from government, I accuse the government for everything. Here people think as if government is a *kalpatarnvu*— government has to give us food, give us everything. Welfarism has gone to such an extent that people here expect government to give everything; people do not help themselves; they accuse government for everything. But the Japanese had put their foot down on such dependence in 1946 itself and said people should not depend on government, they should depend on themselves or on groups.

> "Thus the consumer taxpayer inevitably receives back only part of what he pays out for this purpose."

So, they are discouraged on subsidy by this Ziabatsu principle, their fiscal principle in Japan. This is one of the reasons why Japan is prospering.

Now I will tell you two or three things. I Japan got T.V. in 1953 or 1954 whereas | we got it in India only a few years ago. I In 1954 in Japan their slogan was "full

[Shri G. Swaminathan]

employment" whereas we are talking of full employment now in 1988. They spoke of tax reduction and they accomplished curbs on expenditure long ago. We have not yet accomplished it. In Japan they had a major technological revolution many years ago whereas we are only talking of it here in 1988. They brought about the vital energy revolution In L948. If you have coal and power, if you have energy, then you have full employment. We have not yet accomplished it. In Japan they developed consumer durable industry. We are only talking of it now. In 1960 there were three things which every lapanese wanted to possess, three sacred treasures. The\ said:

"A man should hold a TV set, a wasn-ing machine and a refrigerator."

In the seventies, their three sacred treasures were a car, a colour TV and an air-conditioner. In 1988, I do not know how many Indians can afford the three sacred treasures of the Japanese of the 'sixties' that is, a TV set, a washing machine and a refrigerator. I think we have to go a long way for this. I hope the Government will think over this matter because this is a matter of concern to everybody in this country and not to people belonging to any particular party alone. Thank you, sir.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri H. Hanumanthappa) : Now, Mr. Vikal.

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि यह प्रस्ताव जो सुब्रहमण्यम स्वामी जी ने रखा है कि हमारी आठवीं योजना का प्रारूप कैसा हो उस पर मुझे भी दो-चार शब्द कहने का मौका दिया।

जहां तक इस देश का सवाल है यह गांव में बसा हुआ है। हमारी योजनाओं का प्रारूप गावों की तरफ ही होना चाहिए, गांव की तरफ मुड़ जाना चाहिए ताकि जो शहरों की तरफ आबादी बढ़ रही है वह रोकी जा सके। दिल्ली शहर को आप लें। गांव की आबादी जबर्दस्त यहां आकर बस रही है और पता नहीं क्या-क्या बीमारी फैलती जा रही है। शहरी में आबादी बढ़ रही है, गांवों में बेकारी हो गई है। गांव का बेकार आदमी शहरों में रोजी-रोटी के लिए आता है और मजबूर होकर झुग्गी-झोपड़ी में पड़ा रहता है। इसलिए मेरा कहना है कि आंठवीं योजना गांव की तरफ़ होनी चाहिए।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा देश कृषि पर आधारित देश है। यहां पर 56 कृषि विश्वविद्यालय है। इससे एक-दो ज्यादा या कम हो सकते हैं। वहां पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को टेक्नीकल ट्रेनिंग होती है। कृषि मेले भी जरूर लगने लगे हैं किसान भी आने लगे हैं। साल में एक बार अपने बीज जाते हैं या थोड़ी बातें भी सीख जाते हैं लेकिन वैज्ञानिकों का किसानों की तरफ झुकाव अभी ज्यादा नहीं हुआ है। वह गांवों की तरफ अभी ठीक से पहुंचे नहीं हैं। उनको तेजी से पहुंचा देना चाहिए क्योंकि गांव का किसान अब वैज्ञानिक ढंग से खेती में दिलचस्पी लेने लगा है। उसमें उसकी रुची हुई है। जो विश्वविद्यालयों में नये-नये एक्सपैरीमेंट हो रहे हैं या जो हमारे शोध संस्थान कृषि के बारे में हैं उनका ज्ञान किसानों तक पहुंचना चाहिए। किसान के मेले के अलावा वैज्ञानिकों को भी गांव के साथ जोड़ना चाहिए। यू. पी. में पंतनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं रहा हूं। मैंने देखा है शुरू में अधिकारियों को देहात में जाने में जरूर दिक्कत हुई। कानपुर में कालिज था जिसको यूनिवर्सिटी हमने बनाया। उसके साथ गांव लगाये। गांव के लोग और वैज्ञानिकों को जोड़ा जो हमारे टीचर्स थे, प्रोफेसर थे वे गांव में जाने में थोड़ा हिचकिचाते थे शुरू में, उन्हें दिक्कत होती थी लेकिन

जब उनकी रूचि हो गई और गांव के लोगों ने उसका फायदा उठाया अपने खेती में तो वैज्ञानिकों को भी दिलचस्पी हो गई। चाहे मक्के की फसल हो, गन्ने की फसल हो या गेहूं की फसल हो उसमें तरक्की होने लगी। मेरा कहना है कि गांव के किसान लोग जितनी तेजी के साथ वैज्ञानिकों के साथ जुड़ेगें उतना ही प्रभावकारी असर खेतों पर पड़ेगा।

मैं एक-दो सुझाव और देना चाहूंगा। किसान बिजली बचाओ आंदोलन देश में चलाना ही होगा। बिजली गांव की तरफ़ भेजनी होगी। जापान की अभी स्वामीनाथन जी चर्चा कर रहे थे। मुझे भी जापान जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे पता है वे कितने देशभक्त और कितने ईमानदार हैं। कितने परिश्रमी और कितने अनुशासित हैं। चार-पांच बातें जापान के हर बच्चे में देखने में मिल जाती हैं। शुरू से ही बच्चे में ऐसे संस्कार पैदा किये जाते हैं जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमें स्वेच्छा से यह बात लानी होगी कि बिजली ज्यादा न जलायें विशेषकर सरकारी दफ्तरों में, शादी के मौकों पर। अगर स्वैच्छा से नहीं करते तो सरकार को सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा। अगर राष्ट्र को बचाना है तो देश में जो फ़िजूलखर्ची हो रही है उसको रोकना है। किसान पानी के लिए तरसता है लेकिन हम दूसरी जगह देखते हैं कि पानी फ़िजूलखर्च किया जाता है। हम देखते हैं किस तरह से बिजली का दुरूपयोग दफ्तरों में, शादियों में और होटलों में होता है। हम बिजली का सदुपयोग करके किसानों को दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा किसान तो हमें कुछ दे ही रहा है, हरित क्रांति, सफेद क्रांति। मगर उस बेचारे की आर्थिक हालत बहुत खराब है। उस पर कर्जे का बहुत बोझ है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप भी शायद गांव से आते हैं आपको पता है कोआपरेटिव सोसाइटी का कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, बैंकों का कर्जा, पता नहीं कितने-कितने कर्जे किसानों पर है। सारे देश के किसानों की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है जब कि वह इतनी ज्यादा मेहनत करता है। सब कुछ करने के बाद, हरित क्रांति लाने के बाद उसकी आर्थिक हालत टूट गई है। उसकी तरफ हम को ध्यान देना है।

किसान की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। इसलिए उसके बच्चे एम. ए. और बी. ए पास करने के बाद भी छोटे छोटे शहरों में नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं।

मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। जो हमने मूल्य आयोग बनाया है उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। उनको उनकी मेहनत का, खेतों में जो वे काम करते हैं उसका पूरा परिश्रमिक नहीं मिल रहा है। हमारे वित्त मंत्री सौभाग्य से यहां पर बैठे हुए हैं। किसानों को उनकी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। किसान गन्ना लगाना चाहता है तो पैसे के अभाव में वह गन्ना नहीं लगा पाता हैं। फैक्ट्री वाले उनका पैसा नहीं देते हैं। बैंकों से उनको ऋण नहीं मिल पाता है। यू.पी. में करोड़ रुपया किसानों का पड़ा हुआ है। पूंजीपति और उद्योगपति उनका पैसा लौटाते नहीं हैं। इसलिए मेरा कहना यह हैं कि किसानों का पैसा समय पर दिया जाना चाहिए और उनको बैंकों से ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

जहां तक किसानों की जमीन के मुआवजे का सवाल हैं उनको उचित

[श्री रामचन्द्र विकल]

मुआवजा नहीं मिलता है। उनकी जमीन तो ले ली जाती है लेकिन मुकिन मुआवजा समय पर नहीं दिया जाता है। इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक रूप से किसान के पिछड़ने का एक कारण यह भी है कि उसको समय पर मुआवजा नहीं मिलता है।

मैं कुछ बातें बीमे के संबंध में कहना चाहता हूं। श्री मीर्जा इशादबेग ने उसकी जिक्र किया है। आज जब हमारे देश में भूकम्प आ रहे हैं और बाढ़ आ रही है ऐसे मौके पर बीमे का बहुत महत्व है। कहीं तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। जब किसान के ऊपर कोई विपत्ती आती है तो उसको मदद पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ऐसे मौकों पर जो सहायता दी जाती है वह किसानों तक पहुंचती नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन जिन देशों में खेती पर बोझ कम हुआ उन उन देशों में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इसीलिए गांधी जी ने गांवों में कुटीर उद्योग स्थापित करने पर बल दिया था। अगर किसानों को छोटे छोटे उद्योगों में लगाया जाएगा तो उनका आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हमारे सोलंकी जी किसानों के हित चिन्तक हैं। मुझे याद है सन 1974 में जब हमने कृषि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों की मीटिंग बुलाई थी तो सोलंकी जी ने उसकी प्रोसीडिंग मंगाई थी और उनको पढ़ा था। हमारे वित्त मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं दोनों के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति मौजूद है। वे गरीबों किसानों की तरफ ध्यान देकर गांधी जी के सपने को साकार करने की कोशिश करेंगे। आठवीं योजना का प्रारूप उन्हीं भावनाओं पर हो जिससे इस देश के किसान और मजदूरों का हित हो सके और उनका उद्धार हो। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

PAPER LAID ON THE TABLE

Report of the Ninth Finance Commission and relate paper

THE MINISTER OF FINANCE (SHRl S. B. CHAVAN) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to lay on the Table a copy of the First Report (in English and Hindi) of the Ninth Finance Commission together with an explanatory memorandum showing the action taken thereon, unde[r] Article 281 of the Constitution.

RESOLUTION REGARDING GENERATION OF INCREASED GROWTH RATE FOR SPEEDY DEVELOPMENT OF THE COUNTRY—CONTD.

श्री छोटूभाई रताभाई (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोयहमारें साथी सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जो भावना इस सदन में व्यक्त की हैं उनके साथ मैं सहमत हूं मगर इन भावनाओं को परिपूर्ण करने का जो तरीका उन्होंने बताया है उस तरीके से मैं असहमत हूं। जो हमारे देश का प्लानिंग कमीशन है उसमें जो इसकी पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउन्ड है उसको मैं आपके माध्यम से यहां पढ़ना चाहता हूं:

"The Government of India's intention to create a Planning Commission was announced in the Parlament on 28th February, 1950. The Commission was established on 15th March, 1950, by a Cabinet Resolution.

Planning in India is essentially different from that in countries -like So\iet